बिहार विधान सभा

त्रयोदश सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

27 नवम्बर, 2024

[ग्रामीण विकास - ग्रामीण कार्य - पंचायती राज - जल संसाधन - लघु जल संसाधन - पथ निर्माण - भवन निर्माण श्रम संसाधन].

कुल अल्पसूचित प्रश्न - 7

कूड़ा उठाव हेतु रिक्शा खरीदना

11. **श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (आरा):**

ग्रामीण विकास

हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में दिनांक- 29.01.2024 को प्रकाशित 'कचरा उठाव के खरीदे गये 14879 रिक्शा खराब' शीर्षक को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेगें किः- 1.क्या यह बात सही है कि राज्य के गांवो में लोहिया स्वच्छ भारत अभियान के तहत कचरा उठाव के लिए 78560 पैडल व 5846 ई-रिक्शा की खरीदारी वर्ष 2023 में की गयी थी; 2.क्या यह बात सही है कि गुणवत्तापूर्ण खरीदारी नहीं होने के कारण 17.7 प्रतिशत पैडल एवं 21 प्रतिशत ई-रिक्शा जनवरी 2024 में ही खराब होने एवं कुछ जिलों में रिक्शा खरीदारी के बावजूद इस्तेमाल नहीं होने तथा 12 से अधिक जिलों में पैंडल रिक्शा की खरीदारी अभी तक नहीं होने के कारण कचरा उठाव बंद है , 3.यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार उक्त खरीदे गये रिक्शा की जांच कराने एवं जिन जिलों में रिक्शा की खरीदारी नहीं हुई है वहॉ खरीदारी कराने का विचार रखती है, नही तो क्यों ?

आवेदन स्वीकार करना

12. **श्री विजय कुमार खेमका (पूर्णिया):**

श्रम संसाधन

स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में दिनांक-29 अक्टूबर, 2024 को प्रकाशित ''राज्य के 22 फिसदी कामगारों का नहीं हो पा रहा है निबंधन'' शीर्षक के आलोक में क्या मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि- 1. क्या यह बात सही है कि पूर्णिया जिला सहित राज्य में लगभग 22 फीसदी कामगारों का निबंधन मानक अनुरूप नहीं रहने के कारण विभाग के अधिकारी आवेदन अस्वीकृत कर दे रहे है; 2. क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में एक लाख 90 हजार 489 कामगारों ने आवेदन दिये उसमे 42 हजार 365 आवेदन विभागीय पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया; 3. क्या यह बात सही है कि पूर्णिया जिला में किये गये 1830 आवेदन के विरुद्ध 341 आवेदन ही स्वीकृत किये गये; 4. यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त कामगारों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके निबंधन सम्बन्धी आवेदनों को स्वीकार करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों?

सड़क का चौडीकरण

13. **श्री तारकिशोर प्रसाद (कटिहार):**

पथ निर्माण

दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 07.11.2024 को प्रकाशित "69 सड़क परियोजनाओं को वन विभाग की अनुमति नहीं" शीर्षक के आलोक में क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:- 1. क्या यह बात सही है कि राज्य की 69 सड़क परियोजनाओं के चौड़ीकरण एवं अन्य कार्य हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, अनापति प्रमाण पत्र नहीं दे रहा है; 2. क्या यह बात सही है कि अनापति प्रमाण पत्र नहीं मिलने के कारण उक्त सड़कों पर सुगम वाहन परिचालन में कठनाई हो रही है; 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार उक्त सड़कों के चौड़ीकरण एवं अन्य कार्य हेतु कौन सा कदम उठाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुकदमो का निष्पादन

14. **श्री पवन कुमार जायसवाल (ढाका):**

पंचायती राज

स्थानीय हिन्दी दैनिक पत्र में दिनांक 22 अक्टूबर 2024 को प्रकाशित "सूबे को ग्राम कचहरियों में 14 हजार से अधिक मुकदमे लंबित' शीर्षक के आलोक में क्या मंत्री, पंचायती

राज विभाग, यह बतलाने का कृपा करेंगे किः- 1.क्या यह बात सही है कि राज्य की ग्राम कचहरियों में 14 हजार से अधिक मुकदमे लंबित है, जबकि विभाग द्वारा शत प्रतिशत केस निबटाने का निर्देश दिया गया है; 2.क्या यह बात सही है कि सभी मुकदमे वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक के 'शामिल है, जिसमें 8364 दीवानी मुकदमे और 6413 फौजदारी मुकदमे लंबित हैं; 3.यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार राज्य की ग्राम कचहरियों में लंबित मुकदमो को शत प्रतिशत कब तक निबटारा कराने का विचार रखती हैं, नहीं, तो क्यों?

सड़क का निर्माण

15. **श्रीमती शालिनी मिश्रा (केसरिया):**

ग्रामीण कार्य

क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि- क्या यह बात सही है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत राज्य में कुल 1.18 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़क है जिसमें 10 साल पहले बनी करीब 30 हजार किलोमीटर सड़क है जो टुट चुकी है तथा 65 हजार कि०मी० सड़क के अभी मेन्टेनेंस अवधि (डिफेक्ट) लायबिलिटी पीरीएड में रहते हुए भी एजेन्सियों द्वारा मेन्टेनेन्स का कार्य नहीं किया जा रहा है, यदि हां तो सरकार राज्य के टूटी हुई 30 हजार कि०मी० सड़क बनाने का कबतक विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

निर्माण करना

16. **श्री ललित कुमार यादव (दरभंगा ग्रामीण):**

पंचायती राज

क्या मंत्री, पंचायती राज विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः- 1. क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी प्रखंडों में पंचायत समिति संसाधन केंद्र निर्माण हेतु पंचायती राज विभाग के अनुश्रवण पदाधिकारी के पत्रांक- 5प/ष0रा0वि0आ0-11-01/2022/45(स्वी0) पं0रा0, दिनांक 29.09.2022 द्वारा एक करोड़ रूपये राशि की स्वीकृति दी गई थी; 2. क्या यह बात सही है कि विभाग के उदासीनता एवं उचित मार्गदर्शन नहीं दिए जाने के कारण अभी तक किसी भी प्रखंड में पंचायत समिति संसाधन केंद्र का निर्माण नहीं कराया गया है; 3. यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार कब तक सभी प्रखंडों में पंचायत समिति संसाधन केंद्र का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों?

भवन निर्माण करना

17. **श्री जिवेश कुमार (जाले):**

ग्रामीण विकास

क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे की— 1. क्या यह बात सही है कि इन्दिरा आवास योजना के तहत वर्ष 2012 से 2016 तक राज्य में 4,91,990 आवास का निर्माण होना था जिसमे अभी तक मात्र 3,65,627 आवास का ही निर्माण हुआ है; 2. क्या यह बात सही है कि अभी तक 1,26,363 आवास का निर्माण पेंडिग है; 3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार इन्दिरा आवास योजना के तहत पेंडिग पड़े सभी आवासों को प्रधानमंत्री आवास योजना से अच्छादित कर कबतक आवास निर्माण करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना-800015 .
27 नवंबर , 2024 .

श्रीमती ख्याति सिंह ,
प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा